



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1986/आश्विन 4, 1908

No. 452]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1986/ASVINA 4, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1986

प्रधिसूचना

प्रायकर

सा.का.नि. 1111(अ).—यतः प्राय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए, भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच हुए संलग्न अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया गया है और उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 29 के पैरा 1 में यथापेक्षित अनुसमर्थन दस्तावेजों का पहली प्रगस्त, 1986 को आदान-प्रदान कर दिया गया है;

अतः अब, प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 90 और कम्पनी (साम) संहिता अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रवृत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवम्वादा निवेश करती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबन्ध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

866 GI/86—1

भारत गणराज्य की सरकार

और

कोरिया गणराज्य की सरकार

के बीच

दोहरे कराधान के परिहार तथा प्राय पर करों के संबंध में राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए अभिसमय।

भारत गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार

प्राय पर करों के सम्बन्ध में शुरुआत कराधान के परिहार और राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिख अनुसार हुई है;

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक प्रयत्न दोनों सविधिकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के प्रारम्भ और आने वाले कर

1. यह अभिसमय प्रत्येक सविधिकारी राज्य की ओर से प्राय पर लगाए जाने वाले करों पर लागू होगा, चाहे वे कर किसी भी तरीके से लगाए जाते हों।

(1)

3. जहाँ व्यक्ति से विश्व कोई व्यक्ति, वैराजाफ-1 के उपबन्धों के कारण दोनों संबिधाकारी राज्यों का निवासी हो हो वह उस संबिधाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है। संघेह की स्थिति में संबिधाकारी राज्यों के सखम प्राधिकारी पारस्परिक समुमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

अनुच्छेद 5

स्वायी संस्थापन

1. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, "स्वायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसमें उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्वायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला; तथा
- (च) कोई खान, मेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा ऐसा कोई अन्य स्थान जहाँ से प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हों।

3. इसी प्रकार "स्वायी संस्थापन" पद में कोई भवन स्थल, कोई निर्माण, संयोजन अथवा संस्थापन परियोजना अथवा उसके संबंध में पर्यवेक्षणी गतिविधियाँ भी शामिल हैं, परन्तु वहाँ जहाँ इस प्रकार का स्थल, परियोजना अथवा गतिविधियाँ नौ महीने से अधिक अवधि तक जारी रहती हों।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्वायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्य के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन अथवा गुणवैशिष्ट्य के प्रयोजनार्थ मुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पण्य के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन अथवा गुणवैशिष्ट्य के प्रयोजनार्थ स्टॉक रखना;
- (ग) अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य का स्टॉक रखना;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य का केवल क्रय करने अथवा मूचना संग्रह करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का नियत स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार में केवल विज्ञापन देने, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा अन्य कार्यों के प्रयोजनार्थ, जो अन्य रूप से प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के कार्य हों, के लिए कारोबार का नियत स्थान रखना;
- (च) इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (क) से (ङ) में उल्लिखित क्रियाकलापों के अनन्ततः किसी संयोजन के लिए कारोबार का नियत स्थान रखना बशर्ते कि संयोजन के परिणामतः कारोबार के नियत स्थान के समस्त क्रियाकलाप प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हों।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी स्वतंत्र हैसियत के अधिकता से भिन्न कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तथा एक संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के नाम से संविदाएं सम्पन्न करने के लिए अधिकार का श्राव्य प्रयोग करता हो, तो उन कार्यों के संबंध में, जिन्हें वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियाँ पैराग्राफ 4 में उल्लिखित गतिविधियों तक सीमित न हों, जो यदि कारोबार के किसी नियत स्थान के माध्यम से की गयी हों, तो कारोबार का यह नियत स्थान उस पैराग्राफ के कारण एक स्थायी संस्थापन नहीं होगा।

(1) किसी राज्य का किसी संविदाकारी राज्य से स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी बलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों।

7. मात्र इन तथ्य से कि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य को निवासी हो, किसी ऐसे कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा उससे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य को निवासी हो, अथवा जो उस दूसरे राज्य में (जहाँ किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) अपना कारोबार करती हो, इनसे कोई भी कंपनी खुद किसी दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन सकती।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति में आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।

2. "अचल संपत्ति" पद उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार परिभाषित किया जाएगा जहाँ संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हानत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्त्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अथवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदायगियों के अधिकार; पोत नौकाएं तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाले आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध, किसी उद्यम की अचल संपत्ति से होने वाली आय पर तथा स्वतन्त्र व्यक्ति सेवाओं के निष्पादन के लिए हस्तमाल में आने वाली अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार न करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुआ माना जा सकता है।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधिन रहते हुए, जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, तो प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का ही लाभ समझा जाएगा जिसे, उसके द्वारा प्राप्त होने का, तब अपेक्षा की जात जब वह उन्हीं या वैसे ही परिस्थितियों में, उन्हीं या वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम से पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से कारोबार करता, जिसका यह, एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थाई संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जो स्थाई संस्थापन के प्रयोजनों के लिए किए गए हों जिनमें हम प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किये गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र, और जिनकी स्वीकृति उस संविदाकारी राज्य के अपने आन्तरिक कानूनों के उपबंधों के अन्तर्गत की जाती है, जिस में स्थायी संस्थापन स्थित है।

4. कोई लाभ, मात्र हम लिये स्थायी संस्थापन के कारण हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पक्व वस्तुएं खरीदी गई हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहाँ भाग्य अथवा लाभों में, भाग्य की वे मरें शामिल हों, जिनका इस अधिनियम के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

विमान परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से हुए लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "वायुयान संचालन" पद के अन्तर्गत वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों अथवा अङ्ग्रेजियों (चार्टरर्स) द्वारा वायुयान के जरिये किया जाने वाला व्यक्तियों, पशु-धन, माल अथवा डाक का परिवहन, जिनमें अन्य उद्यमों की ओर से, ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, किराया—आधार पर वायुयान का प्रारम्भिक पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 9

जहाजरानी परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से प्राप्त लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसा संचालन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर, उस राज्य के आन्तरिक कानून द्वारा अन्यथा लगाये जाने वाले कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन-एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 10

सहयोगी उद्यम

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके आर्थिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी गतें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो वेसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई लाभ, जो उन शर्तों के अभाव में ही हाजिर में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु, उन शर्तों के कारण, उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किए जा सकेंगे और तदनुसार कराधेय हो सकेंगे।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. तथापि, ऐसे लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है, जिस राज्य की लाभांश देने वाली कंपनी निवासी है, परन्तु यदि पाने वाला लाभों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर नीचे बताई गई रकम से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभों की सकल रकम का 15 प्रतिशत यदि हितभागी स्वामी एक ऐसी कंपनी है, जिसके पास लाभांश अदा करने वाली कंपनी की पूंजी का प्रत्यक्षतः कम से कम 20 प्रतिशत भाग हो ;

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांश की सकल रकम का 20 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जिनमें से लाभों का भुगतान किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय, शेयरों अथवा ऐसे अन्य अधिकारों से प्राप्त भाग से है, जो लाभ में भागीदार ऋण—दावे नहीं हैं तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त भाग से है, जिन पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कराधान कानून द्वारा शेयरों से प्राप्त भाग के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है, वहाँ स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है, और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, किसी भी स्थिति में, लागू होंगे।

5. जहाँ ऐसी कोई कंपनी, जो एक संबिदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संबिदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरे राज्य की कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा, जहाँ तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी को ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए गए हैं अथवा जहाँ तक कि जिन धाराविधियों के अधिन में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित आधार में प्रभावी रूप में संबद्ध है, वहाँ उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कंपनी के प्रतिनिधि लाभों पर अधिभारित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा प्रतिनिधि लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न हो जाने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

6. ब्याज किसी संबिदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाले स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपखंड, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संबिदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संबिदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह ब्याज दिया गया था जिन पर ब्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 13

रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

अनुच्छेद 12

ब्याज

1. एक संबिदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संबिदाकारी राज्य में भी जिसमें वह उद्भूत हुआ हो और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभावित कर ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबंधों के रहते हुए भी :

(क) जहाँ ब्याज, वास्तविक बैंकिंग कारोबार चला रहे किसी बैंक को अदा किया जाता है जो दूसरे संबिदाकारी राज्य का निवासी है और ब्याज का हितभागी स्वामी है, तो उस संबिदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न होता है, लगाया गया कर ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

(ख) जहाँ ब्याज, संबिदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य की सरकार अथवा उस राज्य के किसी राजनैतिक उप-खंड अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सेंट्रल बैंक अथवा निर्यात-आयात बैंक को अदा किया जाता है तो उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा जिसमें वह उत्पन्न होता है।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त भाग, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और खासतौर पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों के संबंध में प्रदान किये जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं।

5. पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी किसी संबिदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संबिदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार चलाता है, अथवा उस दूसरे राज्य में, वहाँ स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से भावी रूप से संबंधित है। इस प्रकार के मामलों में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 18 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

1. एक संबिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संबिदाकारी राज्य के किस निवासी को अदा की गई रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए दी गई फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए दी गई फीस पर उस संबिदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा नेंगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता, रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक वृत्तियों के किसी भी कारिदाश्ट जिसमें निम्नलिखित में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण में प्रयुक्त होने वाली फिल्मों अथवा टेप भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, व्यापार-चिन्ह, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिये अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी सम्मिलित है।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से प्रवर्धन, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के लिये, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कार्यों की सेवाओं की व्यवस्था करना भी शामिल है, प्रतिफल के रूप में अदायगी करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को अदायगी करने तथा अनुच्छेद 15 में वर्णित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को दी गई अदायगियों से भिन्न, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गई अदायगी सम्मिलित है।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों का हितभागी स्वामी, जो एक संबिदाकारी राज्य का निवासी है, और दूसरे संबिदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहाँ पर स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, और जिस अधिकार, संपत्ति अथवा संसाधन के संबंध में रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 18 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायल्टियाँ और फीस भ्रदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहाँ रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस भ्रदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में अदायगी करने का बचन दिया गया था और उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा अदायगियों का जारी होना, तब रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ अदायगी और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए भ्रदा की गई फीस को रकम ऐसे प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना की ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए, उनकी अदायगी की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके नियम इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में भ्रदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामलों में, अधिक भ्रदा की गई रकम पर, इस अभिसमय के अन्य उपायों की शान में रखा जाएगा, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 14

अंशगत अभिलाम

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित अचल संपत्ति के अंतरण से अथवा ऐसी कंपनी के शेयरों के अंतरण से, जिसकी परि-संपत्तियों में मुख्य रूप से अचल संपत्ति सम्मिलित हो, होने वाले अभिलाम, उस राज्य में कराधेय हो सकेंगे जिनमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलामों पर, जो उस स्थायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति का एक हिस्सा है और जो एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाम पर, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी की दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें एक स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाम भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा ऐसे जलपोषी तथा वायुयानों के अंतरण से, जिन्हें ऐसा उद्यम अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के अन्तर्गत परिचालित करता है तथा इस प्रकार के जलपोषी तथा वायुयानों के संचालन से संबंधित अचल संपत्ति से प्राप्त अभिलाम केवल उस राज्य में कराधेय हो सकेंगे।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी भी संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाम, केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होंगे, जिसमें अंतरणकर्ता एक निवासी है।

5. "अंतरण" शब्द से अभिप्रेत है ऐसे संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार अंतरण जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ

1. ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा जब तक कि उसे अपने कार्यकलापों को सम्पन्न करने के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो। यदि उसके पास ऐसा निश्चित स्थान है, तो केवल उसी आय पर ही उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें कि उस निश्चित स्थान के कारण हुई मानी जा सकती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएँ" पद में विशेषकर स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, गणित-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दन्त चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएँ

1. अनुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के उपायों के अन्वयगत रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त बतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा, जब तक कि उसकी नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रबोधिनिष्ठ राज्य में ही लगेगा यदि:

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित "गिछले वर्ष" अथवा "कराधान वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, कुल मिलाकर 183 दिन में अतिरिक्त की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो; और
- (ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा की ओर से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार द्वारा बढ़न नहीं किया गया हो जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में संयोजित किसी जलपोत पर अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद 17

निदेशकों की फीस तथा उच्च स्तरीय प्रबन्धकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसी कंपनी के उच्चस्तरीय प्रबंधकीय पद के अधिकारी के रूप में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवास है, प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 18

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, लोक मनोरंजनकर्त्ताओं जैसे पियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार अथवा खिलाड़ी के रूप में अपने वैकल्पिक कार्यों से, जिन्हें दूसरे संविदाकारी राज्य में किया जाता है, प्राप्त भाग पर उसी राज्य में कर लग सकेगा।

2. जहाँ मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा उसके वैयक्तिक क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो वहाँ उस आय पर, अनुच्छेद 7 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किये जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध मनोरंजनकर्त्ताओं अथवा खिलाड़ियों द्वारा एक संविदाकारी राज्य में किये गये क्रियाकलापों से प्राप्त पारिश्रमिक अथवा लाभ, वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार की आय पर लागू नहीं होंगे, यदि उस राज्य में उनकी यात्रा को दूसरे संविदाकारी राज्य, किसी राजनैतिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण की सार्वजनिक नियमों से संपूर्ण रूप से सहायता की जाती है।

अनुच्छेद 19

पेंशन

अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 और 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, पिछले नियोजन के प्रतिफल में प्रदत्त पेंशन तथा इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 20

सरकार के कार्य

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक राजनैतिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में दत्त की गयी पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य से ही कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो:

(i) उस राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(ii) सेवाएँ प्रदान करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना था।

(ग) एक संविदाकारी राज्य अथवा एक राजनैतिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के लिए उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दत्त की गई पेंशन पर उसी राज्य में कर लग सकेगा।

(घ) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब कर लग सकेगा यदि वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी है और राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 16, 17 और 19 के उपबंध, एक संविदाकारी राज्य अथवा किसी राजनैतिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये गये कारबार के संबंध में की गई सेवाओं के बारे में प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध, कोरिया के मामले में, बैंक ऑफ कोरिया, निर्यात-आयात बैंक ऑफ कोरिया तथा कोरिया व्यापार संवर्धन निगम द्वारा तथा भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा और संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मान्यता प्रदान किये गये संगठनों द्वारा तथा उनकी सहमति से अथवा किये गये पारिश्रमिक अथवा पेंशनों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त प्रदायगियाँ

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवास है अथवा था, और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, उस दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी:

(क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसे की गई अदायगियाँ; तथा

(ख) उस दूसरे राज्य में "किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "कराधान वर्ष" में जैसी भी स्थिति हो, रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक पर जो वह लाभ और सात सौ हजार कोरियाई वोन अथवा उसके समुल्य भारतीय मुद्रा से अधिक नहीं हो, बशर्त कि ऐसा रोजगार उसके अध्ययन से सीधे संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के लिए किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद का लाभ, केवल ऐसी अवधि तक के लिए उपलब्ध होगा जो शिक्षा अथवा लिए गए प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में, किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद का लाभ, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में पहुँचने की तारीख से लगातार पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 22

प्राध्यापक, अध्यापक तथा शोध छात्र

1. कोई व्यक्ति जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, और जो, उस दूसरे राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान किये गये किसी भी विश्व-विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा उसी प्रकार की दूसरी शैक्षिक संस्थाओं के सामंजस्य पर, उस दूसरे राज्य में ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में केवल अध्यापन अथवा शोध कार्य अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ आते हैं, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए, उस दूसरे राज्य में उसके पहुँचने की तारीख से लगातार दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए, उसके पारिश्रमिक पर कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि इस प्रकार का शोध कार्य मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

अनुच्छेद 23

अन्य प्राय

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय को उन मदों पर, जहाँ कहीं उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, उस दूसरे राज्य में ही कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का प्रयाकरण

1. कोरिया के निवासी के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार निम्न प्रकार से किया जाएगा :

कोरिया से निम्न किसी भी देश में संदेय कर का कोरियाई कर के प्रति खाता जमा के रूप में छूट के संबंध में कोरियाई कर कानून के उपबंधों के अधीन रहने हुए (जिसका इसके सामान्य सिद्धांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा), भारतीय कानूनों के अंतर्गत तथा इस अभिसमय के अनुसार संदेय भारतीय कर (लाभांश के मामले में, उस लाभों के संबंध में देय कर को छोड़कर जिनमें से लाभांश अदा किया जाता है) प्रत्यक्ष अथवा कटौती द्वारा, भारत के अन्दर ओरों से प्राप्त आय के संबंध में, उस आय के संबंध में संदेय कोरियाई कर के प्रति खाता-जमा के रूप में अनुमति दी जाएगी। तथापि, यह खाता-जमा, कोरियाई कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगा जो भारत के अन्दर के ओरों से प्राप्त आय का सम्पूर्ण आय पर कोरियाई कर के साथ हों।

2. पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, "संदेय भारतीय कर" पद में भारतीय कर की उस रकम को सम्मिलित माना जाएगा जो भारतीय कर कानूनों के अनुसार उस स्थिति में संदेय होती, यदि उस पर भारत में आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित उन कानूनों के अनुसार भारतीय कर की छूट अथवा कटौत प्राप्त नहीं होती जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख को लागू थे अथवा अन्य उपबंध जिन्हें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की सहमति से उन कानूनों में संशोधन अथवा परिवर्धन के लिए भारत में बाध में लागू किया जाए परन्तु यह कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम :

(क) अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्लिखित लाभांशों के मामले में ऐसे लाभांशों की कुल रकम के 15 प्रतिशत के बराबर की रकम और, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(ख) में उल्लिखित लाभांशों के मामले में ऐसे लाभांशों की कुल रकम के 20 प्रतिशत के बराबर की रकम;

(ख) अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित व्याज के मामले में, ऐसे व्याज की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम तथा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित व्याज के संबंध में ऐसे व्याज की कुल रकम की 10 प्रतिशत रकम; तथा

(ग) अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित रायल्टियों के मामले में, ऐसी रायल्टियों की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम से अधिक नहीं होगी।

3. भारत के निवासी के मामले में, दोहरे कराधान का परिहार निम्न प्रकार से किया जाएगा।

भारत से निम्न किसी भी देश में संदेय कर को भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में छूट से संबंधित भारतीय कर कानून के उपबंधों के अधीन रहने हुए (जिसका इसके सामान्य सिद्धांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा) कोरिया के कानूनों के अंतर्गत तथा इस अभिसमय के अनुसार, कोरिया के अन्दर के ओरों से प्राप्त आय के संबंध में, प्रत्यक्ष अथवा कटौत द्वारा संदेय कोरियाई कर को (लाभांशों के मामले में, ऐसे लाभों के संबंध में संदेय कर को छोड़कर जिनमें से लाभांश की अदायगी की जाती है) उस आय के संबंध में संदेय भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में माना जाएगा। तथापि यह जमा भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी जो कोरिया के अन्दर के ओरों से प्राप्त आय का सम्पूर्ण आय पर भारतीय कर के साथ हो।

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजनों के लिए "संदेय कोरियाई कर" पद में कोरिया कर की उस रकम को सम्मिलित माना जाएगा जो कोरियाई कर कानूनों के अनुसार उस स्थिति में संदेय होती यदि उस पर कोरिया में आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित उस कानून के अनुसार कोरियाई कर की छूट अथवा कटौत प्राप्त नहीं होती जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख को लागू थे अथवा अन्य उपबंध जिन्हें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की सहमति से उन कानूनों में संशोधन अथवा परिवर्धन के लिए बाद में कोरिया में लागू किया जाए, बशर्ते कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर की रकम :

(क) अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(क) में उल्लिखित लाभांशों के मामले में ऐसे लाभांशों की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम, तथा अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2(ख) में उल्लिखित लाभांशों के बारे में ऐसे लाभांशों की कुल रकम की 20 प्रतिशत रकम;

(ख) अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित व्याज के मामले में, ऐसे व्याज की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम तथा अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित व्याज के मामले में ऐसे व्याज की कुल रकम की 10 प्रतिशत रकम; तथा

(ग) अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित रायल्टियों के मामले में ऐसी रायल्टियों की कुल रकम की 15 प्रतिशत रकम से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद 25]]

[सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तसलंबी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से निम्न अथवा अधिक कष्टकर हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में संचालित जा रहे स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में वैसी ही कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर संचालित जा रहे कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक संविदाकारी राज्य को, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, नागरिक प्रतिष्ठा अथवा पारिवारिक उत्तराधिकारों के कारण कराधान के प्रयोजनार्थ कोई ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत तथा कटौती मंजूर करने के लिए बाध्य करता है जो वह स्वयं के निवासियों को मंजूर करता है।

3. जिन मामलों में अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 12 वा पैरा 7 अथवा अनुच्छेद 13 का पैरा 7 लागू होते हैं, उन्हें छोड़कर व्याज, रायान्तियां तथा अन्य अदायगियों जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को की गई हों वे इस प्रकार के उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, जहाँ नहीं पर कटौति पाने योग्य होंगे जैसे कि वे प्रथमोल्लिखित राज्य के कर निवासियों को अदा की गई हों।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य है एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं, प्रयोजन संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उन कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक कष्टकर हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं :

5. इस अनुच्छेद के उपबंध अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक प्रकार के तथा किस्म के करों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण, उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह, इन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के, जिसका कि वह निवासी है अथवा, यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अन्तर आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य के, जिसका कि वह राष्ट्रिक है, सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला, उन कार्य-वाहियों की पहली अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण इस अभिसमय के प्रतिकूल कराधान हुआ है।

2. सक्षम प्राधिकारी, यदि उसे आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उन मामलों को हल करने का प्रयास करेगा। जो भी करार हो गया हो उसे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में विहित किसी भी समय सीमा के होने हुए भी कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा झगड़े उत्पन्न हो तो, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में भी दोहरे कराधान के अन्तर्करण के लिए परस्पर परामर्श कर सकेंगे जिनकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं है।

4. पूर्वगत पैराग्राफों के अभिप्राय के अंतर्गत महसुस के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी मामलों पर पहुंचने के लिये विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत हो तो ऐसा आदान-प्रदान करना एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

866 C/I/86—2

अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के प्राधिकारी ऐसी सूचना का (जिनमें दस्तावेज भी शामिल हैं) आदान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिसमय के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों के आंतरिक कानूनों के उन उपबंधों को लागू करने के लिये आवश्यक हों, जो इस अभिसमय के अधीन आने वाले करों से, खास तौर पर जानसाजी अथवा इस प्रकार के करों के अपवर्जन को रोकने से संबंधित हैं जहां तक कि उनके अधीन लगाये जाने वाले कर इस अभिसमय के प्रतिकूल न हों। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जिस प्रकार उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। लेकिन यदि सूचना, संश्लेषण करने वाले राज्य में गुप्त हल से गुप्त मानी जाती है, तो वह केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट की जाएगी जो उन करों के निर्धारण अथवा वसूली, उनके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अस्तित्व हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे इस सूचना का सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श द्वारा उन मामलों के संबंध में समुचित हों, तरीके तथा तकनीक विकसित करेंगे जिनके संबंध में सूचना का इस प्रकार का आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहां उचित हो, कर-परिहार के बारे में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जो एक संविदाकारी राज्य को निम्नलिखित के लिये बाध्य करे:

(क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना।

(ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त किए जाने योग्य नहीं है।

(ग) ऐसी सूचना देना, जिनमें कोई व्यापारिक-व्यवसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो (आई. ए. पब्लिक)।

अनुच्छेद 28

राजनायिका अधिकारों तथा कौंसली अधिकारों

इस अभिसमय के अंतर्गत विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष कारणों के प्रावधानों के अंतर्गत, राजनायिका अधिकारियों तथा कौंसली अधिकारियों के राज्य-वार विषय-विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 29

प्रवर्तन

1. इस अभिसमय को अभिवृष्टि की जाएगी तथा अभिवृष्टि दस्तावेजों का निर्माण में अथवा संभव हो, आदान-प्रदान किया जाएगा।

यह अभिसमय अधिवृष्टि के सम्मेलनों के आह्वान-प्रदान को तारीख के बाद 30वें दिन प्रवर्तित होगा।

2. इस अभिसमय का :

(क) कोरिया में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय पर आरम्भ हुआ, हों उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद अतिवासियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर खोत पर रोके गए कर के संबंध में ; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय पर आरम्भ हुआ, हों उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरु पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में

प्रभाव पड़ेगा।

(ख) भारत में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय पर आरम्भ हुआ, हों उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद अतिवासियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर खोत पर रोके गए कर के संबंध में ; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में इस अभिसमय पर आरम्भ हुआ, हों उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरु पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में, प्रभाव पड़ेगा।

अनुच्छेद 30

समाप्ति

यह अभिसमय अधिवृष्टि काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद शुरु होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 जून को अथवा उस से पहले, राजनायिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति का निम्नलिखित नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में यह अभिसमय :

(क) कोरिया में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद अतिवासियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर खोत पर रोके गए कर के संबंध में ; और
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरु होने वाले करधान वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में।

(ख) भारत में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद अतिवासियों को अदा की गई अथवा उनके खाते जमा की गई रकमों पर खोत पर रोके गए कर के संबंध में ; और

- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल के पहले दिन को अथवा उसके बाद शुरु होने वाले पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में, निम्नलिखित हो जाएगा।

जिसे माध्यम में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में आज वर्ष एक हजार नौ सौ पचासी के जुलाई मास के 19 वें दिन को हिन्दी, कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषाओं में मूलतः दो-दो प्रतियों में किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रमाणिक होंगे। तीनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

कोरिया गणराज्य की सरकार
की ओर से

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)
वित्त मंत्री

(वान म्यग की)
विदेश मंत्री

प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में बोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अवबन्धन को रोकने के लिए कोरिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुए अभिसमय पर हस्ताक्षर करने समय, अधोहस्ताक्षरी सहमत हो गए हैं कि निम्नलिखित उपबंध अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे।

1. अभिसमय के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) के संबंध में, यह समझा जाता है कि अभिसमय उस कोरियाई रखा कर पर भी लागू होगा, जहाँ वह आयकर अथवा निगम कर के संबंध में प्रभाविता होता है।

2. अभिसमय के अनुच्छेद 8 तथा 9 के प्रयोजनार्थ यह समझा जाता है कि :

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान और पोतों के संचालन से संबंधित विधियों पर व्याज को भी ऐसे वायुयान और पोतों के संचालन से प्राप्त लाभों के रूप में माना जाएगा ; और
- (ii) एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा चलाए गए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान और पोतों के संचालन के संबंध में, उस उद्यम को, यदि वह भारत का उद्यम है कोरिया में मुख्य वर्धित कर (वैल्यू एडेड टैक्स) से भी छूट प्राप्त होगी, यदि कोरिया का कोई उद्यम है, तो कोरिया में मुख्य वर्धित कर के समान किसी कर से छूट प्राप्त होगी, जो इसके बाद भारत में लगाया जा सकता है।

3. अनुच्छेद 9 के संबंध में यह समझा जाता है कि इसके पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस कराधान वर्ष में अथवा उसके बाद चलाए गए जहाजरानी परिवहन के संबंध में लागू होंगे, जिनमें संविदाकारी राज्यों अथवा उनके प्राधिकृत नामित व्यक्तियों के बीच जहाजरानी परिवहन से संबंधित कोई करार सम्पन्न किया जाता है और प्रभावी होता है।

यह भी समझा जाता है कि जब तक संविदाकारी राज्यों अथवा उनके प्राधिकृत नामित व्यक्तियों के बीच जहाजरानी परिवहन से संबंधित कोई करार प्रवर्तित होता है, तब तक पैराग्राफ 2 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों के संचालन से अर्जित लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें इस प्रकार का संचालन किया जाता है, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर उस राज्य के आन्तरिक कानून द्वारा अन्यथा लगाए गए कर के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

4. अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 और 4 के संबंध में यह समझा जाता है कि उन पैराग्राफों के उपबन्ध उन प्रथम पाठ बयानों के लिये लागू होंगे जिनके लिए यह अभिसमय प्रभावी है लेकिन संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं कि क्या यह अर्थव्यवस्था बचाई जाएगी।

जिसके माध्यम में, अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रस्तावकोष पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वही माध्यम और वैधता होगी जैसे कि वह इस अभिसमय में शब्दों: अन्त स्थापित किया गया हो।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार दो सौ पचास के जुलाई, मान के 19वें दिन को हिराई, कोरियाई तथा अंग्रेजी भाषाओं में मूलतः दो-दो प्रतियों में किया गया, इसके सभी पाठ सामान्य प्रमाणिक होंगे। तीनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से कोरिया गणराज्य की सरकार की ओर से
(विश्वनाथ प्रताप सिंह) (वान-क्युंग ली)

वचन मंत्री

विदेश मंत्री

भारतीय राजदूतावास
सिओल

अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान का प्रस्तावकोष

अधोहस्ताक्षरी, सुधीर तुषाराम देवारे, कोरिया गणराज्य में भारतीय गणराज्य के विशिष्ट राजदूत और पूर्णाधिकारी और कोरिया गणराज्य के विदेश-कार्य मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन व सन्धि ब्यूरो के महानिदेशक सिन की-ओक ने, जो अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिक रूप से प्राधिकृत हैं, आप पर वर्षों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपव्यय को रोकने के लिए, भारतीय गणराज्य की सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच हुए अभिसमय के अनुसमर्थन के दस्तावेजों आदान-प्रदान के प्रयोजनार्थ बैठक की, जिस पर 19 जुलाई, 1986 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए।

उपयुक्त अभिसमय के अनुसमर्थन के अपने-अपने दस्तावेजों की जांच करने के बाद उन्हें उचित और सही रूप में पाये जाने पर उनका आज के दिन आदान-प्रदान किया गया।

जिसके अभिसाक्षर हैं, उन्होंने वर्तमान प्रस्तावकोष पर हस्ताक्षर किए हैं।

सिओल में 1986 के अगस्त, मान के प्रथम दिन, दो प्रतियों में मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में सम्पन्न हुआ, दोनों प्रतियाँ सामान्य प्रमाणिक होंगी।

हस्ता./-

हस्ता./-

(एस. टी. देवारे)

(शिन की-बाक)

भारतीय गणराज्य की सरकार
की ओर से

कोरिया गणराज्य की सरकार
की ओर से

[सं 6937-फा सं 501/22/73 वि क प]

शि. सु. एसडि, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 26th September, 1986

NOTIFICATION

INCOME TAX

G.S.R. 1111(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged, as required by paragraph 1 of Article 29 of the said Convention, on 1st August, 1986 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea,

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have agreed as follows :

Article I

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are :

- (a) In the case of Korea :
 - (i) the income tax ;
 - (ii) the corporation tax; and
 - (iii) the inhabitant tax ;
 (hereinafter referred to as "Korean tax") ;
- (b) In the case of India :
 - (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ;
 - (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) ;
 (hereinafter referred to as "Indian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The Competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention unless the context otherwise requires :

- (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Korea or India as the context requires ;
- (b) the term "tax" means Korean tax or Indian tax, as the context requires ;
- (c) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons which is treated as an entity for tax purposes ;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes ;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (f) the term "competent authority" means, in the case of Korea, the Minister of Finance or his authorised representative; and in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorised representative ;
- (g) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the laws in force in the Contracting State ;
- (h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of this Convention by either Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of the Convention the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him, if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests) ;
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests can not be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode ;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national ;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. In case of doubt the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ; and
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" likewise encompasses a building site, a construction assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than nine months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, the supply of information, scientific research, or any other activity, if it has a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) of this paragraph, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, if a person—other than an agent of independent status to whom paragraph 6 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment by virtue of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the use, enjoyment or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 5 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, which are allowed under the provisions of the domestic law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where income or profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of aircraft in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

3. For the purposes of this Article the term "operation of aircraft" shall include transportation by air of persons, livestock, goods or mail, carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft on a charter basis and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, profits derived from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which such operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 50 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed:

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns directly at least 20 per cent of the capital of the company paying the dividends;
- (b) 20 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term 'dividends' as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article:

- (a) where the interest is paid to a bank carrying on a bona fide banking business which is a resident of the other Contracting State and is the beneficial owner of the interest, the tax charged in the Contracting State in which the interest arises shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest;
- (b) where the interest is paid to the Government of one of the Contracting States or a political sub-division or local authority or the Central Bank or the Export-Import Bank of that State, it shall not be subjected to tax by the State in which it arises.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits and, in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claims in respect of which the interest is paid are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or the fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such cases, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copy-right of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15, in consideration for services of a managerial, technical or consultative nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or perform in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services and paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such cases the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to make the payments was incurred and the payments are borne by the permanent establishment or fixed base, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such cases, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Capital gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6 or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of immovable property, may be taxed in the State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purposes of performing professional services including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base may be taxed in the other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, gains by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property, other than those mentioned in preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. The term "alienation" shall mean alienation in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the "previous year" or "taxation year" concerned, as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic, shall be taxable only in that State.

Article 17

DIRECTORS' FEES AND REMUNERATION OF TOP-LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a Company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by entertainers or athletes if their visit to that State is substantially supported from the public funds of the other Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof.

Article 19

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 20

GOVERNMENT FUNCTIONS

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of service rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who :
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. (a) Any pension paid by or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

- (b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Article 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

4. The provisions of paragraph 1 of this Article shall likewise apply in respect of remuneration or pensions paid, in the case of Korea, by the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea and the Korea Trade Promotion Corporation and in the case of India, by the Reserve Bank of India and the EXIM Bank of India, and by organizations recognized by and agreed between the competent authorities of the Contracting States.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State on :

- payment made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- remuneration from employment in that other State, in an amount not exceeding one million and seven hundred thousand Korean Won or its equivalent in Indian currency during any "previous year" or the "taxation year", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his main education.

2. The benefits of this article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this article for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 22

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. An individual who is or was a resident of a Contracting State immediately before making a visit to the other Contracting State, and who, at the invitation of any university, college, school or other similar educational institution, which is recognised by the competent authority in that other State, visits that other State solely for the purpose of teaching or research or both at such educational institution shall be exempt from tax in that other State on his remuneration for such teaching or research, for a period not exceeding two consecutive years from the date of his first arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 23

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In the case of a resident of Korea, double taxation shall be avoided as follows :

Subject to the provisions of Korean tax law regarding the allowance as a credit against Korean tax of tax payable in any country other than Korea (which shall not affect the general principle hereof), the Indian tax payable (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of India and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within India shall be allowed as a credit against Korean tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Korean tax which the income from sources within India bears to the entire income subject to Korean tax.

2. For the purposes of paragraph 1, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include the amount of Indian tax which would have been payable in accordance with Indian tax laws but for the exemption or reduction of Indian tax in accordance with the laws relating to incentives for the promotion of economic development in India which were in force on the date of signature of this Convention or any other provisions which may subsequently be introduced in India in modification of, or in addition to, those laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting States, provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed :

- in the case of dividends referred to in paragraph 2 (a) of Article 11 an amount of 15 per cent of the gross amount of such dividends and, in the case of dividends referred to in paragraph 2 (b) of Article 11 an amount of 20 per cent of the gross amount of such dividends;
- in the case of interest referred to in paragraph 2 of Article 12 an amount of 15 per cent of the gross amount of such interest and in the case of interest referred to in paragraph 3 (a) of Article 12 an amount of 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- in the case of royalties referred to in paragraph 2 of Article 12 an amount of 15 per cent of the gross amount of such royalties.

3. In the case of a resident of India, double taxation shall be avoided as follows :

Subject to the provisions of Indian tax law regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in any country other than India (which shall not affect the general principle hereof), the Korean tax payable (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) under the laws of Korea and in accordance with this Convention, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Korea shall be allowed as a credit against Indian tax payable in respect of that income. The credit shall not, however, exceed that proportion of Indian tax which the income from sources within Korea bears to the entire income subject to Indian tax.

4. For the purposes of paragraph 3, the term "Korean tax payable" shall be deemed to include the amount of Korean tax which would have been payable in accordance with Korean tax laws but for the exemption or reduction of Korean tax in accordance with the laws relating to incentives for the promotion of economic development in Korea which were in force on the date of signature of this Convention or any other provisions which may subsequently be introduced in Korea in modification of, or in addition to, those laws so far as they are agreed by the competent authorities of the Contracting States, provided that the amount of the tax referred to in this paragraph shall not, however, exceed :

- (a) in the case of dividends referred to in paragraph 2 (a) of Article 11 an amount of 15 per cent of the gross amount of such dividends and, in the case of dividends referred to in paragraph 2 (b) of Article 11 an amount of 20 per cent of the gross amount of such dividends;
- (b) in the case of interest referred to in paragraph 2 of Article 12 an amount of 15 per cent of the gross amount of such interest and in the case of interest referred to in paragraph 3 (a) of Article 12 an amount of 10 per cent of the gross amount of such interest; and
- (c) in the case of royalties referred to in paragraph 2 of Article 13 an amount of 15 per cent of the gross amount of such royalties.

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be constituted as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 7 of Article 13 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same condition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident

or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. This case must be presented within three years from the first Notification of the action giving rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself about to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State.

However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court, proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents and consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Seoul as soon as possible.

The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of the instruments of ratification.

2. This Convention shall have effect:

(a) in Korea:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention is initialled; and
- (ii) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which the Convention is initialled.

(b) in India:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the Convention is initialled; and
- (ii) in respect of other taxes for previous years beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which the Convention is initialled.

Article 30

TERMINATION

The Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

(a) in Korea:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given; and
- (ii) in respect of other taxes for taxation years beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

(b) in India:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given; and
- (ii) in respect of other taxes for previous years beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 19th day of July one thousand nine hundred and eighty five on three original copies each in the Hindi, Korean and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the

Republic of India

(VISHWANATH PRATAP SINGH)
MINISTER OF FINANCE

For the Government of
the Republic of Korea

(WON KYUNG LEE)
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

PROTOCOL

At the moment of signing the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the convention.

1. In respect of subparagraph (a) of paragraph 3 of Article 2 of the Convention, it is understood that the Convention shall also apply to the Korean defence tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax.

2. For the purposes of Articles 8 and 9 of the Convention, it is understood that:

- (i) interest on funds connected with the operation of aircraft and ships in international traffic shall also be regarded as profits from the operation of such aircraft and ships; and
- (ii) in respect of the operation of aircraft and ships in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State, that enterprise, if an enterprise of India, shall also be exempt from the value added tax in Korea and, if an enterprise of Korea, shall also be exempt from any tax similar to the value added tax in Korea, which may hereafter be imposed in India.

3. In respect of Article 9 it is understood that the provisions of its paragraphs 1 and 2 shall apply in respect of shipping transport carried on or after the taxation year in which an agreement related to shipping transport between the Contracting States or their authorized nominees is concluded and becomes effective.

It is further understood that until an agreement related to shipping transport between the Contracting States or their authorised nominees enters into force, paragraph 2 shall read as follows: "profits derived from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which such operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 90 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State."

4. In respect of paragraphs 2 and 4 of Article 24, it is understood that the provisions of those paragraphs shall apply for the first 5 years for which this Convention is effective but the competent authorities of the Contracting States may consult each other to determine whether this period shall be extended.

In witness whereof, the undersigned have signed the present protocol which shall have the same force and validity as if it were inserted word by word in the Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 19th day of July of the year one thousand nine hundred and eighty five on three original copies each in the Hindi Korean and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between the three texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of
the Republic of India

(VISHWANATH PRATAP SINGH)
MINISTER OF FINANCE

For the Government of
the Republic of Korea

(WON KYUNG LEE)
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

भारत व राजदूतवास, सियोल
EMBASSY OF INDIA
SEOUL

PROTOCOL OF EXCHANGE OF INSTRUMENTS OF RATIFICATION

The undersigned, Sudhir Tukaram Devare, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to the Republic of Korea, and Shin Kee-Bock, Director-General of the International Organizations and Treaties Bureau, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea, being duly authorized by their respective Governments, have met for the purpose of exchanging the Instruments of Ratification of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which was signed at New Delhi on 19 July 1985.

The respective Instruments of Ratification of the aforementioned Convention having been examined and found to be in good and due form, the exchange thereof took place this day.

In witness whereof, they have signed the present Protocol.

Done in two originals in the English language, both being equally authentic, at Seoul this first day of August, 1986.

Sd/- Illegible
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

Sd/- Illegible
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA
[No. 6937-F No. 501/22/73-FTD]
V. U. ERADI, Jt. Secy.